1		2	3	4	5
16	Sikkim (at 1982 prices)	9·41	4·66	15·07	11·31
17	Tamil Nadu	(—)11·64	17·04(—)	5·77	4·53
18	Tripura	8·11	N.A.	N.A.	4·10
19	Uttar Pradesh	23·30	1·87	9·06	4·78
20	West Bengal	11·07(—)	4·00(—)	1·69	15·62
	Union Territories				
21	Arunachal Pradesh	6·04	16·58	9·98	3·09
22	Delhi	2·70	5·98	8·30	6·05
23	Goa, Daman & Diu	16·48(—)	1·78	8·04	6·26
24	Pondicherry	4·08	8·48	0·82(—)	1·50

N. A. Not Available ("The figures have not betn supplied by the concerned State Governments)

NOTE 1. Owing to differences in methodology and source material used, the figures for different States are not strictly comparable.

NOTE 2. The States of Meghalaya and Nagaland prepare these estimates at current prices only.

NOTE 3. The Union Territories of Andaman & Nicobar Islands, Chandigarh Dadra & Nagar Haveli, Lakshadweep and Mizoram do not prepare these estimates.

SOURCE: Directorate of Economics & Statistics for estimates.

Death in police custody

2250. SHRI TALARI MANOHAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether attention of the Government have been drawn to the news item which appeared in Times of India dated 26th October, 1986 regarding death in Police custody and if so, the details thereof; and

(b) whether it is a fact that All India Institute of Medical Sciences Doctors are heing pressurised to alter post mortem report and if so, whether a separate magisterial inquiry is likely to be made in such serious allegations above?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Yes, Sir. Chowkidar Dayal Singh, a suspect in a theft case, was arrested and he died in police custody. Inquest proceedings are being conducted. The Inquesting Magistrate has sought the opinion of a Board of three Doctors, one each from All India Institute of Medical Sciences, Lady Hardinge Medical College and University College of Medicine regarding the cause of the death. Sub-Inspector Ranbir Singh in whose custody Dayal Singh had died, has been placed under suspension.

(b) No, Sir.

गरीबी दूर करने की योजना

2251. **श्री राम चन्द्र विकल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय कौन-कौन सी गरीबी दूर करने की योजनाएं चल रही हैं तथा ये कब से चल रही हैं; और

(ख) इन योजनाओं के क्रियान्वयन का ब्योरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) इस समय देश में तीन प्रमुख केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें चल रही हैं जिनका उद्देश्य गरीबी दूर करना है। ये हैं— एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कायक्रम तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम को 1978–79 में 2300 ब्लाकों में शुरू किया गया था और 2 अक्तूबर, 1980 से इसे देश के सभी शेष ब्लाकों में भी शुरू कर दिया गया। 2 अक्तूबर, 1980 से पहले के "काम के बदले अनाज" कार्यक्रम के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया। तथापि, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम 15 अगस्त, 1983 से शुरू किया गया। इसके अतिरिक्त शहरी गरीब वर्ग के लिए एक स्व-रोजगार स्कीम भी 1 सितम्बर, 1986 से प्रारंभ की गई।

(ख) इन स्कीमों के कार्यान्वयन का ब्यौरा निम्न प्रकार हैं :

1 एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम

इस कार्यक्रम में राज्य सहायता और ऋण के जरिए उत्पादनकारी परिसंपत्तियों तथा निदेशों को व्यवस्था द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे परिवारों को स्व-रोजगार-अवसर देने में सहायता की जाती है। आर्थिक सहायता में केन्द्र और राज्यों की समान सहभागिता होती है। छठी योजना तथा 1985–86 के दौरान सहायता प्राप्त लाभभोगी परिवारों की संख्या क्रमशः 16.56 मिलियन तथा 3.02 मिलियन थी।

2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त लाभ-कारी रोजगार का सृजन, स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन तथा लोगों के जीवन स्तर तथा पोषाहार स्थिति में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में भी केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 50:50 के अनुपात में धन लगाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत छठी योजना तथा 1985–86 के दौरान सृजित रोजगार क्रमशः 1775.18 मिलियन श्रम दिवस तथा 316.05 मिलियन श्रम दिवस था।

3 ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम

इस कार्यक्रम के अंतर्गत एक वर्ष में 100 दिवस तक कम से कम हर भूमिहीन श्रमिक परिवार के एक सदस्य को रोजगार गारंटी प्रदान करने की दृष्टि से ग्रामीण भूमिहीनों के लिये रोजगार के अवसर को बढ़ाना और उनमें सुधार करना तथा आधार संरचना को सुदृढ़ करके स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन करना है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई मांगों की पूर्ति हो सके। इस कार्यक्रम के लिए केन्द्र द्वारा धन की पूर्ण व्यवस्था की जाती है। छठी योजना और 1985–86 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत सृजित रोजगार क्रमशः 262.75 मिलियन श्रम दिवस तथा 231.88 मिलियन श्रम दिवस था।

4 शहरी गरीबों के लिए स्व-रोजगार स्कीम

इस स्कीम के अंतर्गत शहरी गरीब जैसे रिक्शावाले, मोची, फेरीवाले, सब्जी व फल विक्रेताओं को सहायता दी जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत, 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर कोई भी पात्र ऋणी 5000 रु० का ऋण ले सकता है। केन्द्र सरकार इसके लिए 25 प्रतिशत की राज सहायता देती है। चालू वर्ष के दौरान इसके अंतर्गत 5 लाख लाभग्राहियों को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव है।

Dividend by Central Government Employees' Consumer Cooperative Society

2252. SHRIMATI RATAN KUMARI: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Central Government Employees' Consu-